करोड़ रुपए

जून, 1981		जून, 1982	जून, 1983
जमा रकमें	5253·97	6464·22	7656·70
ऋण	3031·94	3792·00	4587·78
ऋण: जमा अनुपात	57·7	58·7	59·9

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्र की गई जमा राशियों का वितरण केवल ऐसे क्षेत्रों में किया जाए, बैंकों से उनकी ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के वास्ते अलग से 60 प्रतिशत की ऋण: जमा अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है ।

वित्त मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1512. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन तीनों विभागों के मुख्यालयों में कार्यरत राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं और पिछले वर्ष आयोजित की गई चारों बैठकों में व्यक्तिगत रूप से भाग न लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं और उन बैठकों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उन्होंने भाग नहीं लिया;

(ख) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और उसके प्रचार के कार्यक्रम के अधीन हुई प्रगति का पता लगाने के लिए पिछले वर्ष समिति द्वारा जिन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, उनके नाम क्या हैं और सभी कार्यालयों का निरीक्षण पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे; और

(ग) क्या किसी विभाग ने अधीन कार्यरत सभी कार्यालयों का निरीक्षण पूरा कर लिया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) वित्त मंत्रालय के तीनों विभागों में से प्रत्येक में अलग-अलग राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने पदनामों से नियुक्त किए जाते हैं और वे अथवा उनके प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जो विभिन्न कारणों से समितियों की बैठकों में भाग नहीं ले सके ।

(ख) और (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दिनांक 25 अक्तूबर, 1969 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/69/69–रा. भा. में निर्धारित किए गए हैं और कार्यालयों के निरीक्षण का काम उनमें शामिल नहीं है ।

वाणिज्य मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1513. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कितनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं और पिछले वर्ष के दौरान किस-किस तारीख को उनकी बैठक हुई;

(ख) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित कार्य के विकास और प्रचार की देख-रेख करने के लिए इन समितियों द्वारा, अलग-अलग, कितने विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इन सदस्यों द्वारा टिप्पणियों और आदेशों से सम्बन्धित सरकारी कार्य हिन्दी में किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग में मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर): (क) मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है और साथ ही इसके तीनों सम्बद्ध कार्यालयों में एक-एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। पिछले वर्ष के दौरान जिन तारीखों को उनकी बैठकें हुई वे नीचे दिए गए अनुसार हैं –

क्रम सं.	मंत्रालय/सम्बद्ध कार्यालय	पिछले वर्ष के दौरान जिन तारीखों को उनकी बैठकें हुई ।
1.	मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति	17.1.1983 20.4.1983 6.8.1983 12.12.1983
2.	मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति	27.6.1983 27.9 1983
3.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति	4.1.1983 7.6.1983 4.10.1983
4.	विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वय समिति	शून्य

(ख) किसी का नहीं, क्योंकि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यों के अन्तर्गत उसके द्वारा निरीक्षण किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) समितियों के सदस्य यथासम्भव टिप्पणियों और आदेशों से सम्बन्धित अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करते हैं ।

Animal Plan expenditure of J and K State

1514. SHRI GHULAM RASOOL KAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what are the amounts towards uin.«. al plan expenditure originally approved and the actual expenditure incurred as reported by the State Government of Jammu ana Kashmir from 1974-75 *to* 1980-81; and

(b) what ar© the amounts paid as statutory grant and special grant-in-aid during the same period?

"THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) Statement—I showing the originally approved outlay of J & K and the actual expenditure for the period 1974-75 to 1980-81 as reported by the State Govemment is laid on the Table of the House.

(b) Statement-II showing the grants-in-aid sanctioned to the Government of J & K during the period 1974-75 to 1980-81 by this Ministry is laid on the table of the House.

Statement I

Originally approved outlay of Jammu & Kashmir and actual expenditure as reported by the State Government

(Rs. crores)

Years	Originally approved outlay	Actual expenditure as reported by the State Government.
1974-75	48·00	47·79
1975-76	53·75	58·80
1976-77	79·24	77·05
1977-78	89-68	94·03
1978-79	108·00	97·51
1979-80	118·00	123·55
1980-81	147·48	147·72